

संपादकीय

सिमटते जलस्रोत व जहरीला होता पेयजल

निस्संदेह, पंजाब इन दिनों दोहरे जल संकट से जूझ रहा है। एक ओर जहां अंधाधुंध भू-गर्भीय जल के दोहन से उसका जलस्तर गिर रहा है, वहीं कोटनाशकों व रासायनिक खादों के बेतहाशा इस्तेमाल से पानी जहरीला होता जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय भूजल बोर्ड यानी सीजीडब्ल्यूबी के नवीनतम आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। संस्था के नवीनतम निष्कर्ष बताते हैं कि पंजाब 156.36 फ़ीसदी भूजल दोहन के साथ इसके अत्यधिक इस्तेमाल में देशभर में अग्रणी है। जो इस बात को रेखांकित करता है कि पंजाब में इसके जलस्रोतों का कितने खतरनाक ढंग से अत्यधिक दोहन किया जा चुका है। लेकिन यह संकट यही समाप्त नहीं हो जाता। इस संकट से जुड़ी त्रासदी यह भी है कि सीजीडब्ल्यूबी की नवीनतम वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट-2025 बताती है कि पंजाब में परीक्षण किए गए भूजल के 62.5 फ़ीसदी नमूनों में यूरेनियम सुरक्षित सीमा से कहीं अधिक मात्रा में पाया गया है।

निश्चित रूप से भू-गर्भीय जल के अत्यधिक दोहन और पानी की गुणवत्ता में गिरावट में गहरा संतोध है। दरअसल, अत्यधिक भूजल दोहन से पानी का स्तर नीचे चला जाता है, जिसके चलते गहरे बोरवेल लगाने पड़ते हैं। जो भूगर्भीय रूप से अस्थिर, खनिज-समृद्ध पतलों से पानी खींचते हैं। जो अक्सर यूरेनियम, आर्सेनिक, नाइट्रेट या लवणता से भरी होती हैं। इसके साथ ही, दशकों से चली आ रही सघन कृषि, अधिक सिंचाई वाली फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिये भारी मात्रा में सिंचाई और रासायनिक उर्वरकों की जरूरत होती है। जिसके चलते भूजल व मिट्टी दोनों

ही में प्रदूषकों का रिसाव तेज हो जाता है। इस भयावह संकट को पिछले दिनों राज्यसभा में राजनीतिक आवाज तब मिली, जब सांसद राघव चड्ढा ने पंजाब में विषाक्त जल संकट पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने चेताया था कि भूरा धातुओं और रेडियोधर्मी प्रदूषकों वाला पानी आम लोगों के स्वास्थ्य पर घातक असर डाल रहा है। ऐसा करके उन्होंने देश के नीति नियंताओं को आईना दिखाए का प्रयास ही किया है।

दरअसल, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में इस चिंता को अभिव्यक्त करके, पर्यावरणीय आंकड़ों के जरिये लंबे समय से दिए जा रहे संकेतों को स्पष्ट रूप से उजागर ही किया है। हमें इस बात का अहसास होना चाहिए कि यह अब कोई दूरगामी पर्यावरणीय चिंता नहीं बल्कि हमारे सामने एक उभरती हुई जन-स्वास्थ्य की आपात स्थिति ही है। देश में अकसर उस ट्रेन का जिक्र किया जाता रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में पंजाब के लोग कैंसर के उपचार के लिये राजस्थान के विभिन्न अस्पतालों में जाया करते हैं। जिसे अकसर कैंसर ट्रेन के नाम से पुकारा भी जाता रहा है। निस्संदेह, राज्य के कुओं, बोरवेल या हैंडपंप पर निर्भर लाखों पंजाबियों के लिये, इसका मतलब है कि उनके लिये रोजाना पीने का पानी ही स्वास्थ्य खतरा बन सकता है। जिसके उपयोग से उनके गुर्दों की क्षति, कैंसरकारी घातक प्रभाव और प्रजनन व शारीरिक विकास संबंधी नुकसान हो सकता है। निस्संदेह, इस दिशा में तत्काल निर्णायक कार्रवाई करने की सख्त आवश्यकता है। समय की मांग है कि तत्काल प्रभाव से भूजल के अंधाधुंध दोहन पर सख्त अंकुश लगाया जाए। इसके लिये बेहद जरूरी है कि कृषि क्षेत्र पर ध्यान देकर, कम पानी का उपयोग करने वाली फसलों को प्राथमिकता के आधार पर प्रोत्साहित किया जाए। राज्य के हर शहर व गांव में भूजल गुणवत्ता परीक्षण की सुविधा सहज रूप से उपलब्ध करायी जाए।

प्रदूषित पेयजल के प्रभावी उपचार के साथ ही सुरक्षित जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही औद्योगिक व कृषि प्रदूषकों पर नियंत्रण के लिये पारदर्शी व सख्त कानून व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। वैसे यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वच्छ पेयजल अनंत मात्रा में उपलब्ध नहीं है। हम इसे असीमित संसाधन के बजाय एक नाबुज कीचड़ जैव के रूप में देखें। यदि आज हमने समय रहते हुए पेयजल को सुरक्षित व संरक्षित नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां पेयजल संकट से जूझने को अभिशप्त होंगी। इतना ही नहीं, उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट भी विरासत के रूप में मिलेगा। जिसके लिये वे हमें कभी माफनहीं करेंगी।

एमसीबी जिले में पीएमजीएसवाई से बदला विकास का भूगोल

पहाड़ों, वनाच्छादित और दूरस्थ भौगोलिक स्थितियों के कारण लंबे समय तक संपर्कहीनता की समस्या से जूझता रहा एमसीबी जिला। कई गांव ऐसे थे जहां पहुंचना मौसम के भरोसे होता था। बरसात में सड़कें कट जाती थीं, लोग घरों में कैद हो जाते थे और रोगी, छात्र, किसान सभी कठिनाइयों का सामना करते थे। पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने इस जिले का भूगोल ही बदल दिया। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के अधिकांश गांव पक्की सड़कों से जुड़ चुके हैं और जहां कार्य शेष है, वहां निर्माण युद्धस्तर पर जारी है। यहां सड़कों का जाल सिर्फकंक्रीट या डामर का ढांचा नहीं है बल्कि यह गांवों की नई किस्मत है, ग्रामीण जीवन की धक्कन है और विकास की असली आधार है।

पहाड़ी रास्तों से पक्की सड़क तक एक परिवर्तन की कहानी

एमसीबी जिले की ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों, दुरूह घाटियों और गहरे जंगलों में बसे गांव वर्षों तक मुख्यधारा से दूर रहे। गांवों तक पहुंचने के लिए कभी पगडंडी, कभी नदी का उफ़ान और कभी पहाड़ी रास्तों का सहारा लेना पड़ता था। पीएमजीएसवाई के तहत जब सड़कों का सर्वेक्षण शुरू हुआ, तो ग्रामीणों के बीच उम्मीद की एक नई किरण जागी। आज वही गांव पक्की सड़कों से जुड़ चुके हैं। अब छोटे वाहनों से लेकर एम्बुलेंस और कृषि वाहन तक आराम से पहुंचते हैं। बरसात के मौसम में भी आवागमन बाधित नहीं होता। स्कूल, अस्पताल, बाजार और तहसील सबकी दूरी कम हो गई है। यह बदलाव सिर्फयात्रा में समय घटने का नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता बढ़ने



का है। पहले किसान खेतों से उपज को बैलगाड़ी या अपने सिर पर उठाकर ले जाते थे। कई बार फ़ल मंडी तक पहुंचते-पहुंचते खराब भी हो जाती थी। नई सड़कों का प्रभाव कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी रहा, जिसमें ट्रैक्टर, पिकअप, मिनी ट्रक अब गांव तक पहुंच रहे हैं। धान, कोदो-कुटकी, मक्का, सब्जियां और लघु वनोपज आसानी से मंडी पहुंच रही हैं। परिवहन लागत कम होने से अब किसानों की बचत बढ़ी है। खरीदी समय पर होने से किसानों की आय में स्थायी वृद्धि हुई है। आज किसान गर्व से कहते हैं कि सड़क आई, तो बाजार भी हमारे गांव आ गया।

पहले बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक लाने में कई घंटे लग जाते थे। पहले एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती थी। पर अब स्थिति बदल चुकी है और 108

एम्बुलेंस सीधे घर तक पहुंच रही है, गर्भवती महिलाओं का सुरक्षित संस्थागत प्रसव सुनिश्चित हुआ, टीकाकरण, पोषण व स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी आई, गंभीर मरीजों को समय पर जिला अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। सड़क निर्माण से अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मोबाइल मेडिकल यूनिट की पहुंच आसान और सुविधाजनक हो गया है।

पहले दूरस्थ गांवों के बच्चे बारिश में स्कूल नहीं जा पाते थे। कई बच्चे पहाड़ी रास्तों से डरकर पढ़ाई छोड़ देते थे। अब स्कूल वैन, बसें और ऑटो आसानी से पहुंचते हैं, अध्यापक समय पर स्कूल जा पा रहे हैं। छात्र सुख शिक्षा के लिए कस्बों और शहरों तक आसानी से आ-जा रहे हैं, जिससे ड्राॅपआउट में कमी आया है।

विचार

इसके फायदों को देखते हुए वह खुद ही लोकप्रिय हो जाएगा। हां, फायदों की जानकारी लोगों को जरूर दी जानी चाहिए थी। इसे लेकर गोपनीयता और संभावित निगरानी को लेकर चिंताएं पैदा हुईं, जिनके पीछे भले ही कोई आधार नहीं रहा होगा, पर वे वाजिब थीं। संचार मंत्रालय ने अब बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ‘सरकार ने मोबाइल निर्माताओं के लिए प्री-इंस्टॉलेशन को अनिवार्य नहीं बनाने का निर्णय लिया है।’

भरोसा जीतकर हो सुरक्षा उपायों पर अमल

प्रमोद जोशी

ऐसा नहीं है कि सरकारी एप पर जनता का भरोसा नहीं होता। कोविड के दौरान ‘आरोग्य सेतु’ का देश की जनता ने भरपूर इस्तेमाल किया। वह डिजिटल स्वास्थ्य एप था, जो अब आरोग्य सेतु 2.0 के रूप में और बेहतर हो चुका है। दूरसंचार विभाग ने स्मार्टफ़ोन कंपनियों को ‘संचार साथी’ एप्लीकेशन को अनिवार्य रूप से प्री-लोड करने के अपना आदेश वापस लेकर अच्छा काम किया है। इसे लागू करने का बेहतर तरीका यही था कि लोगों पर छोड़ दिया जाता कि वे चाहें, तो इसे डाउनलोड कर लें और न चाहें तो न करें।

मतलब यह भी नहीं है कि सरकार साइबर अपराधों को रोकने की अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो ले। वस्तुतः यह साख का सवाल है। पिछले सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने देशभर से सामने आए डिजिटल अरेस्ट के मामलों की देशभर में जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा, डिजिटल अरेस्ट तेजी से बढ़ता साइबर क्राइम है। इसमें ठग खुद को पुलिस, कोर्ट या सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो/ऑडियो कॉल के जरिए पीड़ितों, खासकर सीनियर सिटिजन को धमकाते हैं और उनसे पैसे वसूलते हैं। वस्तुतः यह मामला जागरूकता के अभाव की ओर इशारा करता है, साथ ही जनता और सरकार के बीच की दूरी को भी बताता है। कोई व्यक्ति खुद को पुलिस वाला बताकर जब फ़ोन करता है तो सामने वाला डरता है। उसे लगता है कि किसी ग़लत मामले में उसे फंसाया जा सकता है। लोगों के मन में यह डर बहुत गहरा बैठ चुका है। उग़ां ने उसका ही दोहन किया है, अन्यथा जब आपने कोई ग़लती की नहीं है, तो डरने की जरूरत ही क्या है? इसके शिकार साधारण लोग ही नहीं, पड़े-लिखे लोग भी हुए हैं।

ऐसे अपराधों को लेकर मीडिया में जितनी खबरें आई हैं, उतनी अपराधियों पर कार्रवाई की खबरें नहीं आई हैं। पिछले कई साल से यह काम चल रहा है। बड़े स्तर पर संगठित गिरोह इसका संचालन कर रहे हैं। इसका संगठित कारोबार अंतरराष्ट्रीय शक्ल ले चुका है। इसमें धोखाधड़ी वाले कॉल के माध्यम से लोगों को डराकर उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं। अपराधी सरकारी अधिकारियों का रूप धारण करते हैं और पीड़ितों को झूठे कानूनी आरोपों में फंसाने की धमकी देते हैं। इन घोटालों के साथ संगठित अपराध सिंडिकेट जुड़े हैं। इनमें वित्तीय संस्थानों का दुरुपयोग किया जाता है,



जिससे पैसे को क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर उसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है।

ऐसा नहीं है कि सरकारी एप पर जनता का भरोसा नहीं होता। कोविड के दौरान ‘आरोग्य सेतु’ का देश की जनता ने भरपूर इस्तेमाल किया। वह डिजिटल स्वास्थ्य एप था, जो अब आरोग्य सेतु 2.0 के रूप में और बेहतर हो चुका है। वह व्यापक वन हेल्थ एप है, जिसे स्वास्थ्य, कल्याण, चिकित्सा रिकॉर्ड, बीमा और परिवार की देखभाल सभी को एक ही स्थान पर प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसी तरह डिजिटल लॉकर जैसे उपयोगी ऐप भी हैं।

बहरहाल, दूरसंचार विभाग ने 28 नवंबर को जारी प्रारंभिक आदेश में स्मार्टफ़ोन निर्माताओं और आयातकों को नए फ़ोन और पुराने फ़ोनों में भी सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से संचार साथी एप्लिकेशन पहले से इंस्टॉल करने का निर्देश दिया था। इसमें कहा गया था कि एप के कार्यों को अक्षम या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। इसे साइबर सुरक्षा एप्लिकेशन बताया गया, जो उपयोगकर्ताओं को धोखाधड़ी वाले कॉल, संदेशों और चोरी हुए मोबाइल फ़ोन की रिपोर्ट करने की सुविधा देता है। बेशक इन सुविधाओं की नागरिकों को जरूरत है, पर उन्हें लगता

है कि इनकी आड़ में सरकार गुपचुप उनकी निगरानी करने जा रही है। शायद अपने विरोधियों को प्रताड़ित करने का तरीका उसने खोजा है।

आदेश वापस लेने के पहले दिन में, दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार जरूरत पड़ने पर आदेश में बदलाव के लिए तैयार है। सिंधिया ने संसद में कहा, ‘...अगर हमें प्राप्त फ़ीडबैक के आधार पर आदेश में बदलाव करना पड़ा, तो हम इसके लिए तैयार हैं।’ निगरानी संबंधी चिंताओं पर उन्होंने कहा, ‘न तो जासूसी संभव है और न ही की जाएगी।’ एक दिन पहले सिंधिया ने स्पष्ट किया था कि एप वैकल्पिक है और उपयोगकर्ता इसे हटा सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘प्रत्येक नागरिक की डिजिटल सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।’

स्मार्टफ़ोन निर्माताओं एपल और गूगल को, जिनके पास क्रमशः दो सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस और एंड्रॉइड हैं, इस आदेश को लेकर भी आपत्तियाँ थीं। इन कंपनियों का दृष्टिकोण है कि दुनिया में कहीं भी अपने उपकरणों में सरकारी एप्स प्री-लोड करने का इन फ़ोन निर्माताओं का कोई इतिहास या मिसाल नहीं है। इसे लागू करने से परिचालन संबंधी चुनौतियां अलग से पैदा होंगी, क्योंकि इसके लिए उन्हें

दूरस्थ क्षेत्रों में पुल निर्माण से विकास की रफ्तार हुई दुगनी

बस्तर के विभिन्न क्षेत्रों में बन रहे पुल विकास और समृद्धि के ही सेतु बन रहे हैं। नक्सल आतंक से प्रभावित रहे दूरस्थ क्षेत्रों में पुलों के निर्माण से विकास कार्य दुगुनी गति से धरातल पर उतर रहे हैं। आकांक्षी जिला कांकेर में पिछले तीन वर्षों में सेतुओं का तेजी से पूर्ण होता निर्माण सुदूरान्तकों के रहवासीयों के विकास और समृद्धि के भी सेतु बन रहा है। इससे सुदूरवर्ती माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को अच्छी गति मिल रही है।



निब्रा मार्ग के कि.मी. 4/2 मेंदूकी नदी पर नौ करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय पुलों के काम पूर्ण किए गए हैं। अभी जिले में कुल 60 करोड़ रुपए की लागत से 12 वृहद पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। साथ ही कुल 30 करोड़ रुपए लागत के पांच वृहद सेतु कार्य निविदा स्तर पर है, जो कि शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएंगे। इससे 136 गांवों

की 68 हजार से अधिक आबादी लाभान्वित होगी। कांकेर के दूरस्थ छोटेबेठिया-मरबेड़ा-सितमर मार्ग पर कोटरी नदी पर 19 करोड़ रुपए तथा कोयलीबेड़ा-दुता मार्ग पर मेंदूकी नदी पर दस करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से वृहद पुल निर्माणधीन हैं। इनके साथ ही सोनपुर-मरोड़ा मार्ग (बेचाघाट) पर प्रस्तावित पुल निर्माण कार्य की स्वीकृति अंतिम चरण पर है। इन

नया रोजगार और नई उम्मीदें

पीएमजीएसवाई निर्माण ने हजारों ग्रामीणों को रोजगार दिया। सड़क बनने से स्थानीय व्यवसाय, किराना, ढाबा, गैराज आदि, अब खुले परिवहन सेवाओं में वृद्धि हुई, जिससे निर्माण सामग्री की सप्लाई में स्थानीय लोगों को लाभ मिला। आसान हुई, जिससे स्थानीय गाइड और स्टे सुविधा बढ़ी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में यह एक स्थायी और मजबूत निवेश साबित हुआ है।

प्रशासन की सक्रियता-गुणवत्ता और गति दोनों पर जोर

सड़क निर्माण की निगरानी के लिए प्रशासन द्वारा लगातार निरीक्षण, गुणवत्ता परीक्षण और समयबद्ध समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। मानक अनुसार रोड बेस, साइड ड्रेन और सीसी पुल-पुलियों का मजबूत निर्माण, सड़क किनारे सुरक्षा उत्तन व रिफ्लेक्टर, नागरिकों की शिकायतों का त्वरित समाधान मिल रहा है।

गविष्य की कदम शत-प्रतिशत कनेक्टिविटी की ओर

एंड्रेशनल पैकेजों के तहत कई नए मार्ग स्वीकृत हुए हैं, जिनका निर्माण जारी है। लक्ष्य यह है कि जिले का कोई भी गांव सड़क विहीन न रहे, आपदा और बरसात में भी आवागमन बाधित न हो, सभी ग्रामीण सेवाओं की पहुंच अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित हो। एमसीबी जिले में सड़कें अब सिर्फ रास्ते नहीं रहें बल्कि अब विकास, विश्वास और परिवर्तन की सशक्त पहचान बन चुकी हैं।

श्वान की शान और लोकतांत्रिक हलचल

वह तो एक माननीय का पालतू था, जो उतने ही शालीन अंदाज़ में चला, जितने शालीन होने की अपेक्षा कभी-कभी माननीयों से भी कर ली जाती है। उसने न भौंकने की जरूरत महसूस की, न दौड़ने की। युधिष्ठिर के साथ कहते हैं, एक कुत्ता स्वर्ग गया था और देवताओं ने भी उतना हल्ला नहीं मचाया होगा, जितना अब एक कुत्ते के संसद में प्रवेश करने पर मच गया है। सारे अखुबार और टीवी चैनल उसी कुत्ते की सांसों की गणना कर रहे हैं, मानो वह सिर्फ इमारत में नहीं चुसा, लोकतंत्र की रीढ़ में भी हलचल पैदा कर गया हो। यह कोई पहली बार नहीं था जब कुत्ता राष्ट्रीय सुर्खियों में आया हो। कभी सर्वोच्च अदालत ने सड़कों पर घूमते कुत्तों को लेकर दिशानिर्देश जारी किए थे और इस बार सत्ता के गलियारों में आते ही वही प्राणी वैधानिक बहस का नया बिंदु बन गया। संसद में आया यह कुत्ता न आवारा था, न उर्दूड। वह तो एक माननीय का पालतू था, जो उतने ही शालीन अंदाज़ में चला, जितने शालीन होने की अपेक्षा कभी-कभी माननीयों से भी कर ली जाती है।

उसने न भौंकने की जरूरत महसूस की, न दौड़ने की। न उसने टांग उठाकर क्षेत्रीय प्रभुत्व जताया। वह जितनी चुपपी से आया, उतनी ही चुपपी से चला गया, लेकिन देश में शोर ऐसा उठ मानो किसी संवैधानिक संस्था पर हमला हो गया हो। कुत्ते के प्रवेश को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज़ रही। कुछ लोगों को लगा कि यह लोकतांत्रिक मर्यादाओं का अपमान है, जबकि कुछ ने इसे बड़ा मुद्दा बनाने वालों को समझाया कि लोकतंत्र को खतरा कुत्तों से नहीं, उन इंसानों से है जो बिना आवाज उठाए भी काट लेने की क्षमता रखते हैं। बड़े-बड़े टीवी चैनलों ने भी रात भर पैनाल बैठकर कार्यक्रम किए। चुनाव, अर्थव्यवस्था, रोजगार जैसे विषयों पर सीमित दिलचस्पी रखने वाले वही चैनल इस ‘कुत्ता-कांड’ पर विशेषज्ञ बुलाकर बता रहे थे कि यह घटना किस दल को राजनीतिक लाभ पहुंचा सकती है और कौन-सा गुट इससे शर्मिंदा होना चाहिए। सोशल मीडिया ने भी अपने हिस्सा से हास्य का मसाला डाला। एक लोकप्रिय मीम में सवाल पूछा गया— ‘कुत्ता संसद में क्यों गया?’ जबवा था— ‘क्योंकि उसे लगा कि वहां भी उसकी नरल के जीव मिलेंगे।

खास खबर

राष्ट्रव्यापी बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान परीक्षा 7 को

कोरबा। उल्लस नवभारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत राष्ट्रव्यापी बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान परीक्षा 7 दिसंबर को प्रातः 10 बजे से शाम 05 बजे तक जिला के सभी शासकीय प्राथमिक शालाओं में आयोजित की गई है। जिला परियोजना अधिकारी साक्षरता मिशन प्राधिकरण कोरबा ने बताया कि कोरबा जिले को 27960 परीक्षार्थियों का लक्ष्य दिया गया है। कोरबा विकासखंड को 5517, करतला को 6156, कठघोरा को 7106, पाली को 5657 और पोंडौउपरोड़ा को 3524 परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित कराने का लक्ष्य दिया गया है।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 76.75 लाख का 2476 क़िटल धान जब्त

रायपुर। धान अवैध परिवहन और भंडारण पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीते दिनों खसूत निगमनी अभियान चलाया। जिला प्रशासन एवं मंडी विभाग के संयुक्त प्रयासों से सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में अब तक 76.75 लाख रुपये मूल्य का कुल 2476 क़िटल अवैध धान जब्त किया गया है। राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, कृषि उपज मंडी तथा सहकारिता विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा 03 दिसंबर तक लगातार छापेमारी की गई। जिले में निगरानी और जांच अभियान आगे भी लगातार चलता रहेगा।

योगासन खेल प्रतियोगिता का आयोजन 7 को

कोरबा। योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन जिला कोरबा द्वारा 7 दिसंबर को योगासन खेल प्रतियोगिता का आयोजन की तैयारी जोरों से चल रही है। यह प्रतियोगिता गीतांजली भवन, पुराना बस स्टैंड परिसर में होगा। जिसमें प्रतिभागी आयु सीमा कुछ इस प्रकार है। 14 से 17 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, 25 से 35 वर्ष, 36 से 45 वर्ष तक महिलाओं के लिए अलग अलग आयुवर्ग का विभाजन किया गया है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपना अग्रिम पंजीजन दिए गए ऑफिसियल नंबर पर अवश्य कराएँ।

लक्ष्मी राजवाड़े ने किया 157 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन



रायपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत सूरजपुर जिले के विभिन्न ग्रामों में आयोजित विकास कार्यों के भूमि पूजन कार्यक्रमों में शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण अवसरचरना को सुदृढ़ करने हेतु स्वीकृत कुल 157.34 लाख रुपये की लागत वाले निर्माण कार्यों की नींव रखी। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने ग्राम कसकेला में 26.05 लाख रुपए की लागत से सी.सी. सड़क और नाली निर्माण, ग्राम सिलफिन्ही में 76.74 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण, ग्राम गणेशपुर में 37.48 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क एवं नाली निर्माण तथा ग्राम करमपुर में 17.07 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क एवं नाली निर्माण कार्यों का विधिवत भूमि पूजन किया।

बूढ़ातालाब रोड से हटाया गया अतिक्रमण

रायपुर। सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण-मुक्त बनाने के अभियान के तहत कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर टीम प्रहरी ने रायपुर नगर निगम जोन-4 क्षेत्र में बूढ़ातालाब स्थित स्वामी विवेकानंद सरोवर के मुख्य मार्ग से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। यह इलाका लंबे समय से फुटपाथ कब्जे, अवैध ठेलों और निर्माण सामग्री के ढेर की वजह से जाम और अव्यवस्था का केंद्र बना हुआ था। सुबह से ही जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र में बने अवैध कब्जों को विध्वित किया गया। टीम ने दुकानदारों और राहगीरों को क्षेत्र खाली करने का निर्देश दिया।

बाल अधिकारों का हनन करने वालों के खिलाफ आयोग करेगा सख्त कार्यवाही

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। प्रदेश में बच्चों की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने कार्यालय में आयोजित पत्रकारवार्ता में बताया कि बच्चों के अधिकारों का हनन करने वाले लोगों के खिलाफ

आयोग सख्त कार्यवाही करेगा।

स्कूलों के आसपास पान ठेला, गुमटी लगाकार गुटखा सिगरेट एवं अन्य व्यवसन बेचने वालों को स्कूल कैंपस से दुर रखने के लिए प्राचायों को निर्देश दिए गए हैं। जिन बच्चों की देखभाल में लापरवाही बरती जाएगी उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

हाल ही में कोरबा एवं कसडोल में



बच्चों के साथ हुई घटना को लेकर आयोग ने संज्ञान लेकर तत्काल कार्यवाही की।

बाल सुधार गृह का निरीक्षण कर डॉ. शर्मा ने किसी भी प्रकार की क्रूरता करने पर धारा 75 के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कसडोल दौरे का विवरण देते हुए बताया कि वहां वे बाल मेला में शामिल होने शासकीय स्कूल

पहुंची थीं वहां पर गुटखा एवं अन्य कचरों का ढेर देखकर उन्होंने तत्काल प्राचार्य को जमकर फटकार लगाई और भविष्य में इस तरह की स्थिति निर्मित होने पर कार्यवाही की चेतावनी दी है। आयोग गांव शहर में रहने वाले हर बच्चों के अधिकार के लिए सजग है। शिकायत मिलने पर आयोग संज्ञान लेकर त्वरित कार्यवाही कर रहा है।

एसी में होगा फायर डिटेक्शन सिस्टम और सभी गार्ड वैनों में लगेगा हैंड ब्रेक

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के यांत्रिक विभाग ने यात्री सुरक्षा, संचालन दक्षता और विश्वसनीयता को और मजबूत करते हुए एसी कोचों में फायर डिटेक्शन सिस्टम के उन्नत उपयोग तथा गार्ड वैन में हैंड ब्रेक इंडिकेटर की व्यवस्था जैसे दो महत्वपूर्ण तकनीकी सुधार सफलतापूर्वक लागू किए हैं। ये दोनों पहलें रेलवे सुरक्षा मानकों को नई ऊंचाई प्रदान करती हैं और यात्रियों के प्रति भारतीय रेल की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

एसी कोचों में उन्नत फायर डिटेक्शन सिस्टम

फायर डिटेक्शन सिस्टम एक स्वचालित धुआं पहचान एवं अलर्ट व्यवस्था है, जिसे एसी कोचों में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है। सिस्टम के माध्यम से धुआं या आग की प्रारंभिक उपस्थिति का तुरंत पता लगता है और अलार्म सक्रिय हो जाता है, जिससे त्वरित कार्रवाई संभव



होती है तथा किसी भी संभावित जोखिम में उल्लेखनीय कमी आती है।

फायर अलार्म धुआं पहचानते ही स्वतः चेतावनी देने लगता है। कोच के भीतर संभावित आग/धुआं की स्थिति की त्वरित जानकारी ट्रेन संचालक को मिल जाती है। इससे जोखिम को कम करने व समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है। यात्रियों एवं ट्रेन

स्टाफ में सुरक्षा के प्रति जागरूकता में वृद्धि होती है।

राज्योत्सव 2025 में रहा आकर्षण का केंद्र

दुर्ग कोचिंग डिपो द्वारा इस उन्नत फायर डिटेक्शन सिस्टम को राज्योत्सव 2025 में प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया गया, जहाँ इस मॉडल को व्यापक सराहना मिली। आगंतुकों को सिस्टम के डिजाइन, कार्य-सिद्धांत और अलर्ट तंत्र की

प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान की गई, जिससे रेलवे की अगिन सुरक्षा तकनीकों के प्रति आमजन की जागरूकता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

गार्ड वैन में हैंड ब्रेक इंडिकेटर की व्यवस्था

कोचिंग डिपो बिलासपुर द्वारा दो एलएचबी गार्ड वैन में ट्रेन मैनेजर (गार्ड) के केबिन में हैंड ब्रेक इंडिकेटर स्थापित किया गया है। यह सुधार ब्रेक

संचालन की निगरानी को सरल और अधिक विश्वसनीय बनाता है, जिससे ट्रेन संचालन में सुरक्षा को नई मजबूती मिलती है।

रिट्रोफिटमेंट के मुख्य लाभ यह हैं कि इससे हैंड ब्रेक रिलीज की सीधी मॉनिटरिंग हो सकती है। ट्रेन मैनेजर को केबिन से ही ब्रेक की वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है, जिससे गलतियों की संभावना कम होती है। इससे ब्रेक संचालन में सुधार होता है एवं स्टॉफ का वर्कलोड कम होता है। गार्ड एवं ऑपरेटिंग स्टॉफ के लिए मॉनिटरिंग आसान हो जाती है, जिससे संचालन दक्षता और विश्वसनीयता बढ़ती है। यह व्यवस्था गार्ड को परिचालन क्षमता बढ़ाने, मानसिक तनाव कम करने तथा कोचिंग रोक में समग्र सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने में भूमिका निभाती है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के कोचिंग डिपो बिलासपुर एवं दुर्ग द्वारा किए गए ये तकनीकी नवाचार रेलवे की संचालन संरक्षा, विश्वसनीयता और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान में 5 वर्षीय मायरा का अनूठा योगदान

श्रीकंचनपथ समाचार

सुकमा। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत सुकमा जिले में चल रहे जिला क्षय उन्मूलन कार्यक्रम को एक अनोखी और प्रेरणादायक पहल मिली, जब मात्र 5 वर्षीय मायरा केंद्र ने अपने जन्मदिन को जरूरतमंद टीबी ग्रसित बच्चों के नाम समर्पित कर दिया। मायरा ने अपने जन्मदिन पर जिले के 5 टीबी प्रभावित बच्चों को पोषण आहार प्रदान किया और उनके साथ केक काटकर अपना विशेष दिन मनाया। उनके इस मानवीय कदम ने सभी का हृदय जीत लिया।

मायरा के अभिभावकों ने बताया कि लगभग एक वर्ष पहले ही मायरा ने यह फैसला कर लिया था कि वह अपना अगला जन्मदिन टीबी ग्रसित बच्चों के साथ मनाएगी। उसे यह प्रेरणा अपनी मां डॉ. अनुजा केंद्र, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला अस्पताल सुकमा, से मिली।



डॉ. अनुजा ने पिछले वर्ष अपने जन्मदिन के अवसर पर पांच नवजात शिशुओं को गोद लेकर उनके इलाज पूरा होने तक पोषण आहार देने की ज़िम्मेदारी निभाई थी। उसी घटना ने मायरा के मन में सेवा और सहयोग की भावना को जन्म दिया।

जिला क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अधिकारियों ने बताया कि टीबी मरीजों, विशेषकर बच्चों के लिए उच्च पोषण आहार अत्यंत आवश्यक है। सही पोषण उन्हें बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है और उनकी रिकवरी तेज होती है। इस तरह

की व्यक्तिगत पहलें टीबी मुक्त भारत अभियान को मजबूती देती हैं और समाज में जागरूकता फैलाती हैं।

मायरा की पहल ने यह साबित किया कि सेवा करने के लिए उम्र मायने नहीं रखती। एक 5 साल की बच्ची द्वारा टीबी प्रभावित बच्चों की मदद करना समाज के लिए प्रेरणादायक उदाहरण है। कार्यक्रम में मौजूद स्वास्थ्य टीम और अभिभावकों ने मायरा के कदम की सराहना की और कहा कि ऐसे प्रयास टीबी के खिलाफ लड़ाई को नई गति प्रदान करते हैं।

निश्चय मित्र बनकर आप भी कर सकते हैं सहयोग

जिला क्षय उन्मूलन केंद्र सुकमा ने नागरिकों से अपील की है कि वे टीबी मरीजों के पोषण और सहयोग के लिए ‘निश्चय मित्र’ बनकर अभियान से जुड़ें। इच्छुक व्यक्ति जिला क्षय उन्मूलन केंद्र, सुकमा से संपर्क कर सकते हैं और किसी जरूरतमंद मरीज की सहायता

प्रधानमंत्री आवास निर्माण में देश में सबसे आगे निकल गया छत्तीसगढ़ - किरण देव

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार के दो साल के पूरे होने जा रहे कार्यकाल को संकल्पों की सिद्धि और उपलब्धियों का प्रामाणिक दस्तावेज बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर गरीब के सिर पर पक्की छत का जो संकल्प भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ‘मोदी की गारंटी’ में व्यक्त किया था, वह गारंटी पूरी करके प्रदेश सरकार ने विश्वसनीयता अर्जित की है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के दो साल के महत्वपूर्ण निर्णयों एवं उपलब्धियों का विस्तार से जिक्र कर बताया कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक आयोजित कर मोदी की गारंटी के अनुरूप 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में योजना शुरू होने से अब तक 26 लाख से अधिक पीएम आवास मंजूर किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वर्ष 2016-26 तक कुल प्राप्त लक्ष्य 26,27,223 आवासों के विरुद्ध 24,22,571 आवासों की स्वीकृति कर 16,72,002 हितग्राहियों के आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है।

आवास निर्माण की गति बढ़ाते हुए लगभग 2,000 आवास



प्रतिदिवस निर्माण किया जा रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को पक्के आवास से लाभाश्वित किया जा रहा है जिसके तहत अभी तक कुल 33,217 आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इसी प्रकार मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत प्रदेश

के आवासहीन 38,798 परिवारों को आवास स्वीकृत किए गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने कहा कि प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए 15 हजार आवास स्वीकृत के गए हैं।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित सुरक्षा कैंप की 10 कि.मी. की परिधि में आने वाले गांवों में नियद नैलानार योजना के तहत 327 गांवों में 13,788 घरों और शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत 1.32 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार आवास से आजीविका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत 8000 से अधिक महिला स्व-सहायता समूह की दीर्घायें सेंटरिंग प्लेट एवं निर्माण सामग्री की आपूर्ति के कार्य से लखपति दीदी बनीं।

उन्होंने कहा कि अटल डिजिटल सुविधा केंद्र 4500 से अधिक ग्राम पंचायतों में पीएमएवाय-जी के हितग्राहियों की किरतों का आहरण आसान हुआ है।

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में स्वास्थ्य सेवाओं के बढ़ते कदम

सुरक्षित सिजेरियन शुरू, लंबे सफर से मिली निजात

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इससे जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार हो रहे हैं। जिले में सिजेरियन डिलीवरी सुविधा की सफल शुरुआत एक प्रमुख उपलब्धि के रूप में सामने आई है। पूर्व में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को जिला चिकित्सालय राजनांदगांव रेफर किया जाता था, जिसके लिए लंबा सफर तय करना पड़ता था। जिले में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता, अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रसव कक्ष और सुव्यवस्थित ऑपरेशन थिएटर से



स्थानीय स्तर पर ही सुरक्षित एवं त्वरित प्रसव सेवाएँ उपलब्ध हो गई हैं। जिले में अब तक 15 सफल सिजेरियन प्रसव किए जा चुके हैं, जिससे मातृ-शिशु स्वास्थ्य को नई मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व

अभियान के अंतर्गत एनीमिया, गर्भावस्था-प्रेरित उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थायरॉइड तथा रक्त संबंधी समस्याओं को जैसी उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। जिले के स्वास्थ्य केंद्रों में 24

घंटे चिकित्सा सेवाएँ सुनिश्चित की गई हैं, ताकि गर्भवती महिलाओं को किसी भी समय त्वरित उपचार प्राप्त हो सके। जिले में सिजेरियन सुविधा उपलब्ध होने से ऐसी गर्भवती माताओं को सुरक्षित और निश्चिंत देखभाल उपलब्ध कराई जा रही है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निबांध एवं निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाना विभाग की प्राथमिकता है। इसी क्रम में 01 दिसम्बर 2025 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर में एक सफल सिजेरियन डिलीवरी तथा 16 महिलाओं की नसबंदी सर्जरी संपन्न की गई। यह उपलब्धि जिले की स्वास्थ्य टीम की दक्षता और सेवाभाव का प्रमाण है।

राष्ट्रीय शालेय भारोत्तोलन में रिहान ने 273 किलो उठाकर जीता स्वर्ण

श्रीकंचनपथ समाचार

राजनांदगांव। 16 वर्ष के रिहान खान ने राष्ट्रीय शालेय वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्णपदक जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जिला भारोत्तोलन संघ के संरक्षक व छ.ग. प्रदेश भारोत्तोलन संघ के उपाध्यक्ष अजय वास्तव ने बताया ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश 69वीं नेशनल स्कूल गेम्स वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता, जो 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक खेलो इंडिया ऑडिटोरियम, ईटानगर में आयोजित हुई।

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले जय भवानी व्यायाम शाला के दिग्विजय स्टेडियम प्रशिक्षण केंद्र के उभरते हुए वेटलिफ्टर रिहान खान ने 98 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर एक

ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। ज्ञात हो कि रिहान जिला प्रशासन द्वारा ग्रीष्मकालीन वेटलिफ्टिंग प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से इस खेल के प्रति लगाव बढ़ा और विशेष ट्रेनिंग से तराशा गया। प्रतियोगिता के दौरान रिहान खान ने अपनी अद्भुत शारीरिक क्षमता, उकृष्ट तकनीक और दृढ़ मानसिक संतुलन का परिचय देते हुए— स्टेज में 118 किलो, क्लीन एंड जर्क में 155 किलो, कुल 273 किलो भार उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रिहान की यह शानदार उपलब्धि उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन, निरंतर प्रशिक्षण और खेल के प्रति सच्ची लगन का परिणाम है। रिहान ने न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे राजनांदगांव जिले को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है।

गंजोपन से मुक्ति

मात्र 1 घंटे में

COMPLETE FAMILY SALON

हेयर रिप्लेसमेंट, 100% संतुष्टि की गारंटी

पहले बाद में

CUT N SHINE

93009-11331

गंगोली बैगल्स के सामने, जयसवाल इलेक्ट्रॉनिक के बाजू में इंदिरा मार्केट, स्टेशन रोड, दुर्ग (छ.ग.)

GST NO. 22AHMPB9621P1Z2

PH.: 07388-4060131

अनुप ट्रेडर्स

आर्टिफिशियल ज्वेलरी के विक्रेता

लिंक रोड, केम्प-2, पावर हाउस, भिलाई

मो. 09826389666, 8839749539



द राजा साब से आया बोमन ईरानी के बर्थडे पर नया पोस्टर, प्रभास ने भी किया एक्टर को जन्मदिन विश

प्रभास स्टारर हॉरर फैंटेसी फिल्म द राजा साब के मेकर्स ने बोमन ईरानी के जन्मदिन को खुद एक सिनेमाई पल में बदल दिया। फैंस के लिए इससे बड़ा सरप्राइज क्या होगा, जब टीम ने इस दिग्गज अभिनेता का एक बिल्कुल नया लुक पोस्टर रिलीज कर दिया। इस पोस्टर ने ना सिर्फ सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी, बल्कि इंडस्ट्री में भी एक्साइटमेंट की लहर दौड़ा दी। प्रभास ने एक्टर का पोस्टर शेयर कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है।

फिल्म में बोमन ईरानी एक साइकेट्रिस्ट, हिप्नोटिस्ट और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की भूमिका निभाते नजर आएंगे। उनका किरदार बुद्धि और रहस्य के अनोखे संगम में लिपटा हुआ है। ट्रेलर में उनका एक झलकभर सीन पहले ही दिखा चुका है कि वो प्रभास के किरदार को सम्मोहित करते हैं, जो कहानी के पहले बड़े मोड़ की शुरुआत बनता है।

जन्मदिन पर रिलीज हुआ यह स्पेशल पोस्टर फिल्म के साइकोलॉजिकल पहलू की अब तक की सबसे झलक दिखाता है। गहरे, सम्बिर रंगों में, हाथ में छड़ी लिए, बोमन ईरानी का यह अवतार ऐसे ईशान की तरह दिखता है जो अनदेखी दुनिया की परतों में उतर चुका है। इस मौके पर मेकर्स ने बोमन ईरानी के लिए एक खूबसूरत नोट भी शेयर किया, जिसमें उनके

किरदार के कई अनकहे राजों की झलक दिखाई देती है। कैप्शन में लिखा गया, जो हकीकत और अनजाने के बीच खड़ा है। टीम द राजा साब की तरफ से बोमन ईरानी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। पोस्टर शेयर करते हुए प्रभास ने भी बोमन ईरानी को

जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं बोमन ईरानी सर, आने वाला साल शानदार हो। प्रभास की दमदार मौजूदगी और बोमन ईरानी की गहरी, बौद्धिक गंभीरता के साथ द राजा साब 2026 की सबसे बड़ी और चर्चित रिलीज में से एक बनकर उभर रही है। ऐसे में बोमन ईरानी का यह बर्थडे पोस्टर फिल्म के रहस्यों का पड़ा उठाने वाली पहली दस्तक बन गया है।

फिल्म को मुरुगटी ने लिखा और निर्देशित किया है। इसका निर्माण पीपूल मीडिया फैक्ट्री और आईबीवाई एंटरटेनमेंट ने किया है। फिल्म में मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार, संजय दत्त और बोमन ईरानी अहम किरदारों में नजर आएंगे। द राजा साब 9 जनवरी 2026 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी।



डीपनेक टाइटफिटेड आउटफिट में अनन्या पांडे का सिजलिंग अवतार सोशल मीडिया पर छाया, खूबसूरती ने बढ़ाया इंटरनेट का तापमान!

बॉलीवुड की यंग और स्टाइलिश एक्ट्रेस में शामिल अनन्या पांडे एक बार फिर अपने लेटेस्ट लुक को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में वह जीक्यू ड्रैफ्ट में स्पॉट हुईं, जहां उनका बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अनन्या का ये यूनिक और सिजलिंग अवतार देखने के बाद फैंस लगातार उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे।

इवेंट के दौरान अनन्या ने एक बेहद स्टाइलिश और यूनिक आउटफिट कैरी किया। उनका अपर पार्ट डीप नेक और टाइट-फिटेड डिजाइन में है। जिसमें नेट फैब्रिक और वाइट स्टोन का खूबसूरत काम किया गया है। यह ड्रेस उन पर न सिर्फ एलीगेंट लग रही है, बल्कि उनकी फिगर को भी परफेक्ट तरीके से हाईलाइट कर रही है।

नीचे की ओर यह आउटफिट फ्लोइड डिजाइन में है, जिसने पूरे लुक को और भी ग्रेसफुल बना दिया। अनन्या का यह मॉडर्न स्टाइलिश अवतार सोशल मीडिया पर इंटरनेट का तापमान बढ़ा रहा है।

अपने आउटफिट को और खास बनाने के लिए अनन्या ने उसी कलर का एक कोट भी कैरी किया है। इस स्टाइलिश टच ने उनके पूरे लुक को काफी क्लासी बना दिया। स्टेटमेंट ईयररिंग्स, शाइनी मेकअप और खुले बालों के साथ एक्ट्रेस ने अपना ग्लैमरस लुक कंप्लीट किया।

उनकी हर तस्वीर में फैशन और स्टाइल का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, जिसे देखकर फैंस एक बार फिर उनके दीवाने हो गए हैं, जिसका सीधा उदाहरण उनके कमेंट बॉक्स में फैंस की तारीफें साफ बता रहीं हैं।

अनन्या पांडे इंडियन हो या वेस्टर्न हर तरह के आउटफिट को आसानी से कैरी करने के लिए जानी जाती हैं। उनके स्टाइलिश लुक्स अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और कुछ ही मिनटों में चर्चा का विषय बन जाते हैं। उनकी फैशन चॉइसेज हमेशा ट्रेंडी रहने के साथ-साथ यूथ के लिए स्टाइल इंस्पिरेशन भी बन जाती हैं।

काम की बात करें तो अनन्या पांडे इन दिनों कार्तिक आर्यन के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म तू मेरी में तेरा, में तेरा तू मेरी को लेकर काफी बिजी हैं। यह फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है और फैंस इसे लेकर काफी एक्साइटेड हैं।

बहरहाल, इस तरह अनन्या पांडे एक बार फिर अपने फैशन गेम के जरिए लाइमलाइट में हैं और उनका ये नया सिजलिंग अवतार हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर फैंस दिलखोल कर प्यार लुटा रहे हैं।

विजय देवरकोंडा से शादी की चर्चाओं पर रश्मिका मंदाना ने दी प्रतिक्रिया जवाब सुन फैंस हुए उत्साहित

पिछले कुछ वक्त से रश्मिका मंदाना काम से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में बनी हैं। ये चर्चाएं रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी को लेकर हो रही हैं। लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि रश्मिका और विजय अगले साल यानी 2026 की शुरुआत में शादी के बंधन में बंध जाएंगे। हालांकि, रश्मिका या विजय ने अब तक इन खबरों की पुष्टि नहीं की है। अब रश्मिका ने अपनी शादी की खबरों पर प्रतिक्रिया दी है। हालांकि, एक्ट्रेस ने पूरी तरह से कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है।

हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के साथ बातचीत के दौरान

रश्मिका ने अपनी आगामी फिल्मों और वर्कफ्रंट के साथ-साथ अपनी शादी की चर्चाओं पर रिएक्ट किया। इस दौरान जब रश्मिका से पूछा गया कि क्या वह विजय से अपनी कथित शादी की पुष्टि या खंडन करना चाहती हैं? तो इस पर एक्ट्रेस ने कहा कि मैं शादी की पुष्टि या खंडन नहीं करना चाहती।

मैं बस इतना कहूंगी कि जब इस बारे में बात करने का समय आएगा, तब हम करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि वह अपने फैंस या मीडिया के साथ कुछ भी साझा करने से पहले थोड़ा समय लेना चाहती हैं। रश्मिका की इस प्रतिक्रिया के बाद दोनों की शादी को लेकर अटकलें और भी तेज हो गई हैं।

फरवरी में शादी करने की है चर्चाएं

कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा फरवरी में शादी के बंधन में बंध सकते हैं। दोनों की शादी उदयपुर में होगी। रिपोर्ट्स में यहां तक कहा गया कि रश्मिका शादी की तैयारियों के लिए उदयपुर में इंतजाम तक देखने जा चुकी हैं।

अक्टूबर में विजय-रश्मिका ने की थी सगाई

रश्मिका और विजय की सगाई की खबरें अक्टूबर में काफी चर्चा में रही थीं। हालांकि, दोनों में से किसी ने भी इन्हें स्वीकार या खारिज नहीं किया और न ही कोई फोटोज सामने आई। लेकिन बाद में विजय की टीम ने हिंदुस्तान टाइम्स को पुष्टि की कि दोनों ने सगाई कर ली है। टीम ने यह भी पुष्टि की कि कपल फरवरी 2026 में शादी के बंधन में बंध जाएंगे। अब रश्मिका के शादी की खबरों को खारिज न करने के बाद इन चर्चाओं को और भी बल मिलता है।

अवसर साथ नजर आते हैं विजय-रश्मिका

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने साथ में ‘गीता गोविंदम’ और ‘डियर कॉमेरेड’ जैसी फिल्मों

में काम किया है। इसी दौरान दोनों एक-दूसरे के करीब आ गए। इसके बाद से ही दोनों के बीच अफेयर की चर्चाएं आती रहती हैं। दोनों अक्सर कई मौकों पर साथ भी देखा जाता है। दोनों साथ में ही छुट्टियां मनाने भी जाते हैं। हालांकि, इसके बावजूद दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया है।



देकर रिव्यू

लिखवाए जाते हैं, न तो इसे लिखने वाला निष्पक्ष रह पाता है और न कलाकार को सच्ची प्रतिक्रिया मिलती है, जिससे वह आगे सुधार कर सके। इससे सबकी क्रिएटिविटी और ग्रोथ रुक जाती है।

एली अवराम ने बतायी हुमा डोल के पीछे अपने सपनों की कहानी, बोलीं-प्रिंसेस की तरह कर रही थी महसूस

बॉलीवुड और इंटरनेशनल म्यूजिक के फैंस के लिए हुमा डोल एक यादगार म्यूजिक वीडियो बन गया है। यह गाना न सिर्फ अपने खूबसूरत संगीत के लिए चर्चा में है, बल्कि इसके पीछे की कहानी भी किसी सपने की तरह है। अभिनेत्री एली अवराम ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि कैसे यह प्रोजेक्ट उनके लिए दो बड़े सपनों को सच करने जैसा रहा।

एली अवराम ने कहा कि उन्होंने हमेशा चाहा था कि वह मोरक्को के सुपरस्टार गायक साद लमजार्रेड के साथ किसी म्यूजिक वीडियो में काम करें। उनके लिए यह मौका लंबे समय से एक सपना बनकर रहा था। उन्होंने कहा, जब मैंने साद लमजार्रेड का एक सुपरहिट अरबी गाना सुना था, तब से ही मन में यही इच्छा थी कि एक दिन उनके साथ काम करूंगी।

यह सपना आखिरकार हुमा डोल के जरिए सच हो गया। गाने को एक साल पूरा होने पर जब उनसे यादों के बारे में पूछा गया, तो एली ने कहा कि उनके दिमाग में सेट की एनर्जी और

उत्साह समेत कई यादें ताजा हो गईं। उन्होंने कहा, मेरे इस अनुभव ने दो सपनों को पूरा किया। पहला सपना तो साद लमजार्रेड के साथ काम करने का था और दूसरा सपना था कि मैं किसी पुराने जमाने की कहानी में एक प्रिंसेस जैसा लुक अपनाकर अभिनय करूं। हुमा डोल ने मेरे इन दोनों सपनों को पूरा किया। मैं शूटिंग के दौरान सच में खुद को एक प्रिंसेस की तरह महसूस कर रही थी।

एली ने कहा, जब म्यूजिक वीडियो की टीम ने मुझे कास्ट करने के लिए संपर्क किया, तब एहसास हुआ कि बड़े सपने देखने से कभी डरना नहीं चाहिए। अगर आप अपने सपनों को लेकर गंभीर रहते हैं और उन्हें महसूस करने की इच्छा रखते हैं, तो एक दिन वह सच हो सकते हैं।

मेरे इस अनुभव ने साबित कर दिखाया कि सपने सच में पूरे हो सकते हैं। हुमा डोल गाने को लेकर एली ने बताया कि म्यूजिक वीडियो शूट करना उनके लिए किसी फिल्म बनाने से कम नहीं लगता, क्योंकि इसमें सिर्फ अभिनय ही नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस और इमोशन भी देना पड़ता है। उन्हें उम्मीद है कि आगे भी उन्हें ऐसे ही शानदार और जादुई म्यूजिक वीडियो करने का मौका मिलेगा।



बस्तर में शांति का नया अध्याय

नक्सल मुक्त इलाकों में वानिकी बन रहा रोजगार का प्रमुख जरिया

श्रीकंचनपथ न्युज

रायपुर। बस्तर जिले के सुदूर वनांचल में बसे क्षेत्र चांदमेटा, मुण्डागढ़, छिन्दगुर और तुलसी डोंगरी जो कभी नक्सल गतिविधियों के गढ़ माने जाते थे, अब विकास और शांति का नया अध्याय लिख रहे हैं। जिन पहाड़ियों और जंगलों में कभी नक्सलियों की ट्रेनिंग हुआ करती थी, वहीं आज वन विभाग स्थानीय युवाओं को वानिकी कार्यों का प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार उपलब्ध करा रहा है।

इन इलाकों में लंबे समय तक नक्सलियों के प्रभाव तथा उनसे जुड़े लोगों द्वारा कानूनों की गलत व्याख्या ने ग्रामीणों को विकास की मुख्यधारा से दूर रखा। शासन के प्रति अविश्वास का वातावरण बना दिया गया। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं।

ग्रामीणों ने इन तत्वों की वास्तविक मंशा को समझ लिया है और अब वे दूसरों को लड़ाई में अपना समय और भविष्य गंवाने को तैयार नहीं हैं। वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा लगातार किए जा रहे संवाद, जागरूकता और विश्वास निर्माण ने ग्रामीणों का नजरिया



बदला है। स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों को उनके ही गांव के आसपास वानिकी कार्यों में रोजगार देकर न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत की जा रही है, बल्कि उन्हें सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाया जा रहा है।

ग्राम मुण्डागढ़ के समीप स्थित बांस वनों का इस वर्ष वैज्ञानिक तरीके से वन-उपचार किया गया है। ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे इस

कार्य से लगभग 20 लाख रुपये का तत्काल रोजगार सीधे उनके बैंक खातों में पहुँचेगा। आने वाले तीन वर्षों में लगभग 01 करोड़ 37 लाख रुपये के अतिरिक्त रोजगार की संभावना है। इस क्षेत्र से प्राप्त 566 नेशनल टन बांस के उत्पादन का शत-प्रतिशत लाभार्थ वन प्रबंधन समिति के माध्यम से ग्रामीण विकास में ही खर्च किया जाएगा। छिन्दगुर और चांदमेटा के पहाड़ी क्षेत्रों में

इस वर्ष प्रवरण सह सुधार कार्य के तहत बीमार, वृद्ध और मृत वृक्षों को हटाकर जंगल का उपचार किया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को 32 लाख रुपये का तत्काल रोजगार मिल रहा है।

काष्ठ उत्पादन से प्राप्त आय का 20 प्रतिशत लाभार्थ भी गांव की समिति को मिलेगा। अगले 6 वर्षों में लगभग 43 लाख रुपये का अतिरिक्त रोजगार वन उपचार के माध्यम से उपलब्ध होगा। इसके अलावा वन विभाग ग्रामीणों से सतत संपर्क में रहते हुए उनकी आवश्यकताओं का समाधान भी कर रहा है।

ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरण, समिति सदस्यों को टी-शर्ट उपलब्ध कराना जैसी जरूरतें तुरंत पूरी की जा रही हैं। वन मंडलाधिकारी उत्तम गुप्ता ने कहा कि केंद्र समय भय और हिंसा की पहचान रहे थे इलाके आज शांति, आजीविका और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं।

वानिकी कार्यों के माध्यम से जल, जंगल एवं जमीन का संरक्षण करते हुए ग्रामीणों को स्थायी आजीविका उपलब्ध कराई जा रही है। बस्तर के नक्सल मुक्त गांव अब साबित कर रहे हैं कि जब विकास और विकास साथ आते हैं, तो परिस्थितियाँ बदलना केवल समय की बात होगी।

वाटरशेड महोत्सव: जल संचयन पर रील बनाओ, इनाम पाओ प्रतियोगिता

जशपुर जिले में विभिन्न गतिविधियों का हो रहा आयोजन

श्रीकंचनपथ न्युज

रायपुर। भारत सरकार भूमि संसाधन विभाग द्वारा राज्य शासन के सहयोग से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - जलग्रहण विकास घटक अंतर्गत वाटरशेड महोत्सव का आयोजन 19 नवंबर से 19 दिसंबर 2025 तक किया जा रहा है। राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में आयोजित इस महोत्सव के तहत जशपुर जिले में परियोजना स्तर पर जमदान, लोकार्पण, भूमिपूजन, जागरूकता कार्यक्रमों के साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है।

वाटरशेड महोत्सव के अंतर्गत राज्य स्तरीय सोशल मीडिया प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में चार रील विजेताओं को 50-50 हजार रुपये तथा 100 फोटोग्राफी विजेताओं को 1-1 हजार रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। चार विजेता रीलों में से तीन रीलें जल संचयन से संबंधित परियोजना क्षेत्र में निर्मित संरचनाओं पर आधारित होंगी, जबकि एक रील बागवानी एवं कृषि वानिकी गतिविधियों पर आधारित होगी। यह प्रतियोगिता 31 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी।



प्रतिभागी 30 से 60 सेकंड की रील या शीर्षक सहित फोटो तैयार कर सकते हैं, जिसमें जल संचयन संरचनाओं-जैसे चेकडैम, स्टापडेम, नाला बंधान, डबरी, सामुदायिक तालाब, ढीले बोल्टर से बने गेबियन ढांचे आदि-को प्रदर्शित करना होगा। साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के तहत विकसित बागवानी, पौधरोपण अथवा कृषि गतिविधियों को भी शामिल किया जा सकता है। अपनी सामग्री सामाजिक माध्यमों पर पोस्ट करते समय प्रतिभागियों के लिए निर्धारित हैशटैग #डब्ल्यूडीसी.पीएमकेएसवाई.वाटरशेडमहोत्सव.2025 का उपयोग अनिवार्य होगा। पंजीकरण के

दौरान प्रतिभागियों को अपने सामाजिक माध्यम पोस्ट का लिंक भी महोत्सव पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिसके पश्चात सफल पंजीकरण का पुष्टिकरण ई-मेल प्राप्त होगा। प्रतियोगिता अर्वाधि समाप्त होने के बाद 31 जनवरी 2026, शाम 6 बजे तक, प्रतिभागियों को अपने पोस्ट की रीच, दृश्य, सहभागिता, पसंद एवं टिप्पणियों का स्क्रीनशॉट पोर्टल पर जमा करना होगा। विभागीय वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।

अपलोड करना होगा सामग्री-

प्रतिभागी को 30-60 सेकंड की रील अथवा शीर्षक सहित फोटो तैयार कर सामाजिक माध्यम पर पोस्ट करना होगा। सामग्री में जल संरक्षण से जुड़ी संरचनाएँ तथा डब्ल्यूडीसी.पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत विकसित कृषि एवं बागवानी गतिविधियाँ शामिल होनी चाहिए। इसके बाद प्रतिभागी को निर्धारित हैशटैग के साथ सामग्री पोस्ट कर उसका लिंक महोत्सव पोर्टल पर अपलोड करना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने पर प्रतिभागी को पुष्टिकरण ई-मेल प्राप्त होगा।

जशपुर जिले में एक गांव बनेगा मॉडल सोलर विलेज चयन समिति ने शुरू की चयन प्रक्रिया

श्रीकंचनपथ न्युज

रायपुर। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जशपुर जिले में एक ग्राम को मॉडल सोलर विलेज के रूप में विकसित किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। जिला स्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर रोहित व्यास के मार्गदर्शन में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

भारत सरकार द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार मॉडल सोलर विलेज के लिए उन राजस्व ग्रामों का चयन आवश्यक है जिनकी आबादी 5,000 से अधिक हो। जशपुर जिले में ऐसे ग्रामों की संख्या 10 से कम होने के कारण, जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रथम 10 सर्वाधिक आबादी वाले ग्रामों के मध्य छह माह की प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। इसी के आधार पर अंतिम मॉडल सोलर विलेज का चयन किया जाएगा।

दिशा-निर्देशों के अनुसार जिस ग्राम में सरकारी एवं गैर-



सरकारी माध्यमों से सर्वाधिक सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित होगी, उसे मॉडल सोलर विलेज के रूप में प्रार्थमिकता दी जाएगी। इसी क्रम में जिले के 10 सर्वाधिक आबादी वाले ग्राम बटईकेला, सना, कांसाबेल, पण्ड्रापाट, तुडैंग, कामारिमा, घोघर, तपकरा, दुलदुला और फरसाबहार को प्रतिस्पर्धा हेतु सूचीबद्ध किया

गया है। इन ग्रामों में सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने एवं मूल्यांकन के लिए छह माह की अवधि निर्धारित की गई है।

चयनित ग्राम के समग्र विकास हेतु 2 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी. आर.) तैयार कर 15 मार्च 2026 तक ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को प्रेषित की जाएगी।

श्रीकंचनपथ न्युज

रायपुर। केंद्र सरकार के अमृत मिशन के तहत संचालित महत्वाकांक्षी पहल 'वुमेन फॉर ट्री' छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण का प्रभावी मॉडल बनकर सामने आ रही है। बालोद जिले में इस योजना का सफल क्रियान्वयन राज्यभर में महिला शक्ति की भागीदारी से हरियाली एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है।

योजना के अंतर्गत बालोद जिले के 08 नगरीय निकायों में अब तक 6,950 पेड़ लगाए जा चुके हैं। वृक्षारोपण के साथ-साथ पौधों की देखभाल, सिंचाई, सुरक्षा और नियमित रखरखाव की जिम्मेदारी महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपी गई है। इस प्रत्यक्ष भागीदारी ने पौधों के संरक्षण दर में



उल्लेखनीय वृद्धि की है और स्थानीय स्तर पर पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है।

महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'वुमेन फॉर ट्री' योजना के तहत 66 महिलाओं को नियमित कार्य प्रदान किया गया है। प्रत्येक महिला कार्यकर्ता को प्रति माह 8,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, जिससे उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। इन महिलाओं को कार्य के लिए आवश्यक सामग्री जैसे-साड़ी, जैकेट, जूते और संपूर्ण टूलकिट

(फवड़ा, कुदाली, बेलचा, धमेल) भी उपलब्ध कराई गई है। कई महिलाओं ने बताया कि इस आय से वे अपने बच्चों की शिक्षा और घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो रही हैं।

जिला प्रशासन ने बताया कि आने वाले समय में वृक्षारोपण के क्षेत्र को और विस्तृत किया जाएगा तथा अधिक से अधिक महिलाओं को इस अभियान से जोड़ कर नए रोजगार अवसर विकसित किए जाएंगे। पौधों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं

महिलाओं को डिजिटल व मोबाइल बैंकिंग पर दिया गया विशेष प्रशिक्षण

दंतेवाड़ा। जिले के नियत नेहानार योजना के अंतर्गत ग्राम ककाड़ी एवं नहाड़ी, ग्राम पंचायत नहाड़ी, ब्लॉक कुआकोंडा में 03 दिसंबर 2025 को डिजिटल एवं मोबाइल बैंकिंग विषयक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया।

स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में महिला स्व सहायता समूहों को मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल लेन-देन, ऑनलाइन सेवाओं के सुरक्षित उपयोग एवं सरकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से प्राप्त करने संबंधी जानकारी दी गई।

इस संबंध में मुख्य प्रशिक्षक शिव बघेल (लीड बैंक मैनेजर, एसबीआई) ने बताया कि यदि बैंक खाता आधार से लिंक हो जाता है, तो महतारी वंदन योजना सहित अन्य लाभ सीधे खातों में प्राप्त हो सकते हैं तथा महिलाएँ अपने मोबाइल से लाभ की स्थिति की पुष्टि भी कर सकती हैं।

जिले में किसानों से पारदर्शिता के साथ सुगमतापूर्वक हो रही धान खरीदी

श्रीकंचनपथ न्युज

रायपुर। विष्णु के सुशासन में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में किसानों से पारदर्शिता के साथ सुगमतापूर्वक धान खरीदी की जा रही है। कलेक्टर कुन्दन कुमार के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा जिले के 66 सहकारी समितियों के 105 धान उपार्जन केंद्रों में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उपार्जन केंद्रों में उपलब्ध कराई गई सुविधाओं से किसानों को धान विक्रय करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है और उनका धान आसानी से विक्रय हो रहा है।

पथरिया विकासखण्ड के कपुवा उपार्जन केंद्र में धान विक्रय करने पहुंचे किसान रतिराम चतुर्वेदी ने बताया कि उन्होंने इस वर्ष 88.80 क्विंटल धान का विक्रय किया है। उन्होंने कहा कि इस बार केंद्रों में व्यवस्था और भी सरल, सुविधाजनक एवं पारदर्शी है। इलेक्ट्रॉनिक तौल, बारदाना की व्यवस्था, टोकन तुरह हाथ ऐप से धान की सुविधा, पेपजल, छाया सहित तमाम सुविधाएँ उपलब्ध



कराई गई है। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की सुविधा तथा 3100 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य का लाभ मिलने से किसानों को आर्थिक मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि किसान-हितैषी नीतियों एवं बेहतर व्यवस्थाओं से किसानों का प्रशासन पर भरोसा और भी मजबूत हुआ है। श्री चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं जिला प्रशासन को किसानों के हित में उत्कृष्ट व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु धन्यवाद दिया।

गौरतलब है कि शासन के निर्देशानुसार पंजीकृत किसानों से

प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी और 31 सौ रुपये के हिसाब से प्रति क्विंटल धान की राशि दी जा रही है। इससे न केवल किसानों के फसलों का उचित दाम मिल रहा है, बल्कि किसानों का मान भी बढ़ा है। आसान भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए समितियों में माइक्रो एटीएम की सुविधा एवं किसानों को एटीएम कार्ड एवं चेक प्रदान किया गया है, इससे किसानों की जरूरी आवश्यकताएं पूरी होने के साथ ही उनके हक का पैसा उन्हें मिल रहा है। किसान आर्थिक रूप से समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

दिव्यांगजन अपने जीवन में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और समाज की मुख्यधारा से जुड़े हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी

श्रीकंचनपथ न्युज

महासमुंद। दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने, उन्हें समान अवसर एवं अधिकार प्रदान करने तथा उनके सामर्थ्य से परिचित कराने के उद्देश्य से 03 दिसंबर को जिला प्रशासन, समाज कल्याण विभाग एवं समग्र शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का आयोजन सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महासमुंद में किया गया। कार्यक्रम में कुल 450 दिव्यांग हितग्राही, स्कूली विद्यार्थी एवं सहयोगी शामिल हुए।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने मां सरस्वती के तैल्य चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि दिव्यांगजन हमारी समाज की महत्वपूर्ण ताकत हैं। उनमें अद्भुत क्षमता, साहस और जीवदत्ता है। जरूरत है कि समाज उन्हें समान अवसर प्रदान करे और उनके कौशल को मंच मिले। राज्य



सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है तथा हर संभव सुविधा और सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि दिव्यांगजन अपने जीवन में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और समाज की मुख्यधारा से जुड़ें। इस दौरान समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित संस्था फेंचुन फाउण्डेशन नेत्रहीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करमापटपर बागबाहारा के विद्यार्थियों ने मनमोहक राजगीत प्रस्तुत किया।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में नगरपालिका उपाध्यक्ष देवीचंद राठी, जनपद पंचायत महासमुंद उपाध्यक्ष हुलसी चन्द्राकर, महेंद्र सिक्का, शरद पवार, पाषंद ईश्वरी भोई, अपर कलेक्टर रवि साहू मौजूद थे।

कार्यक्रम में विद्यालयीन दिव्यांग विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम नृत्य, गायन की प्रस्तुति दी गई। इसके अलावा खेल-कूद, टॉक शो, फेंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके साथ ही अपने क्षेत्र में

उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिव्यांगजनों एवं दिव्यांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थाओं को अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिह्न प्रदाय कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में 10 दिव्यांग हितग्राहियों को मोटरआईड ट्रायसायकल, 05 को ट्रायसायकल, 05 को व्हील चेयर, 05 दिव्यांगजनों को श्रवण यंत्र, 03 दिव्यांगजनों को छड़ी का वितरण किया गया। अतिथियों द्वारा कार्यक्रम में सम्मानित दिव्यांगजनों, अधिकारी-कर्मचारियों को नशामुक्त भारत अभियान अंतर्गत शपथ दिलाई गई।

उक्त कार्यक्रम उप संचालक समाज कल्याण संगीता सिंह के मार्गदर्शन में एवं डीएमसी रेखराज शर्मा, स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारी-कर्मचारी तथा अशासकीय स्वैच्छिक संस्थाओं के कर्मचारियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। मंच संचालन राजू चंद्राकर सचिव ग्राम पंचायत परसदा ब द्वारा किया गया।

CAR DECOR

House Of Exclusive
Seat Cover,
Car Stereos Matting &
Sun Control Film &
Other Accessories

Shop No.3 Nafish Tower.
Opp. Indian Coffee House,
Akashganga, Bhilai

Mo.9300771925, 0788-4030919

K. Satyanarayan

SAIRAM

Mobile Accessories

मोबाइल शॉप में
कार्य करने हेतु
लड़कों की
आवश्यकता है

7000415602

Shop No. 78, Himalaya Complex, Supela, Bhilai

ROCKEY INDUSTRIES

FURNITURE PALACE

Deals in: (Steel & Wooden)
Luxury & Imported Furniture

Akash Ganga, Supela, Bhilai Ph. 2296430

चौरसिया ज्वेलर्स

आकर्षक सोने चांदी के अग्रगण्य के निर्माता एवं विक्रेता

बेन्टक्स एवं ग्राहल उपलब्ध यहां
उचित व्याज दर पर गिरवी रखी जाती है

मुक्तिधाम रोड, रामनगर, सुपेला, भिलाई

9827938211, 9827171332

Jaquar Roca

Sanitarywares, Tiles,
CPVC Pipes &
Bathroom Fittings etc.

Supela Market, Bhilai

PH. 0788-4030909, 2295573

► पीएम आवास के 1073 हितग्राहियों को नये आवास की चाबी सौंपी

► बलौदाबाजार में कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल भवन, तिल्दा में नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं

श्रीकंचनपथ न्यूज़

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम सुहेला में आयोजित कार्यक्रम में 195.26 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सीगात दी। कार्यक्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के 1073 हितग्राहियों को आवास की चाबी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत तीन हजार महिलाओं को गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना अंतर्गत पाँच हजार किसानों को अधिकार अभिलेख तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को सामग्री और राशि के चेक प्रदान किए।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ध्येय है कि हर घर में पक्का मकान, शौचालय, शुद्ध पेयजल और प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ पहुँचे। उसी उद्देश्य को साकार करने के लिए हमारी सरकार जनता के हित में वचनबद्ध होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बने 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और हम रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। सरकार बनने से पहले प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी में जो वादे किए गए थे, उन्हें हम एक-एक कर पूरा कर रहे हैं।



मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश में 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी हो रही है। तैदुपत्ता संग्रहण की दर बढ़ाकर प्रति मानक बोरा 5,500 रुपये कर दी गई है। किसानों को दो वर्ष का बकाया बोनस भी प्रदान किया जा चुका है। महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ बड़ी संख्या में महिलाओं को मिल

रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत हर घर को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना में बड़ी मात्रा में सस्मिडी भी मिल रही है, इसलिए अधिक से अधिक लोग अपने घरों में सोलर पैनल स्थापित कर लाभ उठाएँ। उन्होंने जिले में प्रशासन की 'हम होंगे कामयाब' पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि

युवाओं को उनकी रुचि के अनुसार प्रशिक्षित कर उनके बेहतर भविष्य के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनसे अब तक 500 से अधिक युवाओं को लाभ मिला है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास की नई

ऊँचाइयाँ छू रहा है और बड़े-बड़े कार्य सहजता से पूरे हो रहे हैं। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में अकेले 100 करोड़ रुपये से अधिक की सड़कों की स्वीकृति मिली है।

मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम के दौरान सुहेला में नवीन महाविद्यालय की स्थापना, तिल्दा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन, बलौदाबाजार में शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल भवन एवं नवीन व्यावसायिक परिसर का निर्माण करने की घोषणा की। उन्होंने जिले के 50 धान उपाजन केंद्रों में किसानों के लिए 10-10 लाख रुपये की लागत से शोड निर्माण तथा सुहेला तिगड्डे में तीनों सड़कों पर एक-एक किलोमीटर तक डिवाइडर निर्माण एवं लाइट लगाने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री साय ने जिन विकास कार्यों का लोकार्पण किया, उनमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत 12.87 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 1073 आवास, तथा लगभग 7.74 करोड़ रुपये की लागत से आमाकोनी, हथबंद, पौसरी, सेम्हराडीह और खपराडीह में निर्मित जल प्रदाय योजनाएँ शामिल हैं। भूमिपूजन के प्रमुख कार्यों में 49.17 करोड़ रुपये की लागत से बलौदाबाजार- रिसदा-हथबंद मार्ग मजबूतीकरण, 20.98 करोड़ रुपये की लागत से बलौदाबाजार के रिसदा बायपास मार्ग,

15.59 करोड़ रुपये की लागत से बलौदाबाजार में इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, 8.60 करोड़ रुपये की लागत से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत 717 आवास तथा 8.04 करोड़ रुपये की लागत से कोल्हान नाले के पार सुगेरा एनिकट निर्माण शामिल हैं।

कार्यक्रम में 5 करोड़ रुपये से अधिक की हितग्राहीमूलक सामग्री एवं चेक वितरण किया गया। इसमें मुख्य रूप से सायबर प्रैंड प्रकरण के 27 लाख रुपये की वापसी, श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं में 83 लाख रुपये का वितरण, 8333 छात्रों को 4.25 करोड़ रुपये की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, महिला स्व सहायता समूहों एवं 'सक्षम' योजना अंतर्गत 16 महिलाओं को 25 लाख रुपये, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 10 हितग्राहियों को 9.69 लाख रुपये तथा 'हम होंगे कामयाब' योजना अंतर्गत 60 हितग्राहियों को 6.81 लाख रुपये का भुगतान शामिल है।

इस अवसर पर बलौदाबाजार-भाटापारा जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष रायपुर नवीन अग्रवाल, पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा, महिला आयोग की सदस्य लक्ष्मी वर्मा, जनपद अध्यक्ष सिमगा दीलत पाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

सफलता के लिए निरंतर सीखना, कौशल निखारना और आत्मविकास अनिवार्य - रामनाथ कोविंद

अनुशासन, नवाचार और अपनी संस्कृति से जुड़ाव यही है सफल भविष्य की कुंजी: मुख्यमंत्री साय

श्रीकंचनपथ न्यूज़

रायपुर। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के छठवें दीक्षांत समारोह का आयोजन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के मुख्य आतिथ्य में गरिमामय वातावरण में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल रमन डेका ने की। अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विशिष्ट अतिथि उपमुख्यमंत्री अरुण साव तथा उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य डॉ. दिवाकर नाथ वाजपेयी उपस्थित रहे। समारोह में 64 शोद्यार्थियों को शोध इपाधि, 92 गोल्ड मेडल एवं 36950 स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि दी गई।

विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्नातक छात्रों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ दीं और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने युवा पीढ़ी की ऊर्जा और आत्मविश्वास की सराहना करते हुए कहा कि भारत आज दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी है और वर्तमान युवा इसका ऐतिहासिक साक्षी और भागीदार हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय से स्नातक होना शिक्षा की पूर्णता नहीं है, बल्कि इक्कीसवीं सदी में सफलता के लिए निरंतर सीखना, कौशल निखारना और आत्मविकास अनिवार्य है।

पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि देश के विश्वविद्यालयों में बेटीयों शिक्षा के क्षेत्र में कई बार बेटों से आगे निकल रही हैं और इस विश्वविद्यालय के स्वर्ण पदक विजेताओं में भी बेटीयों की संख्या उल्लेखनीय है। उन्होंने विद्यार्थियों, विशेषकर



पदक विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि उनकी यह उपलब्धि केवल उनकी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे माता-पिता का त्याग, परिवार का सहयोग और गुरुओं का अमूल्य मार्गदर्शन भी निहित है। यह हर विद्यार्थी के लिए एक सुनहरा यादगार पल है, जिसे वे जीवनभर याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि-कभी यह मत सोचिए कि आप पीछे रह गए हैं। यदि आप प्रयास करना नहीं छोड़ते, तो आप हमेशा पहले स्थान पर हो सकते हैं। उन्होंने छात्रों से अपने सपनों को साकार करने के लिए परिश्रम करने, भारतीय संस्कृति, मूल्यों और जड़ों से जुड़े रहने और योग व विज्ञान जैसी भारतीय विरासत को अपनाने का आह्वान किया।

राज्यपाल रमन डेका ने कहा कि जीवन में अनेक चुनौतियाँ आती हैं, जिनमें कभी-कभी हम गिरते भी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हर बार स्वयं को संभालकर फिर से खड़ा होना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि जीवन में गिरावट से भयभीत न हों और हमेशा उठने का साहस रखें। राज्यपाल ने अनुशासन को जीवन में सफलता की मजबूत नींव बताते

हुए कहा कि जीवन एक सुंदर यात्रा है, और इसे उद्देश्यपूर्ण, सकारात्मक और सार्थक ढंग से जीना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर ध्यान आकर्षित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज तनाव एक बड़ी चुनौती बन चुका है। इसलिए योग, ध्यान और नियमित शारीरिक गतिविधि को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों से यह भी आग्रह किया कि वे जीवन में ऐसा कार्य चुनें जिसमें तनाव कम हो, पारदर्शिता हो और जिससे स्वयं, समाज और राष्ट्र का सकारात्मक परिवर्तन संभव हो। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सफलता केवल डिग्री से नहीं, बल्कि सीखने की निरंतर इच्छा से तय होती है। दुनिया तेजी से बदल रही है, और जो युवा अपनी संस्कृति की जड़ों से जुड़े रहते हुए तकनीक, नवाचार और मेहनत का मार्ग चुनते हैं, वहीं कल का भारत गढ़ेंगे। जीवन में अवसर हमेशा बाहर नहीं मिलते, कई बार हमें स्वयं अवसर बनाना होता है। अनुशासन, लगन और सकारात्मक दृष्टि ही वह शक्ति हैं, जो हर साधारण क्षण को असाधारण उपलब्धि में बदल देती है।

उन्होंने कहा कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह पीढ़ी छत्तीसगढ़ की और पूरे देश की नई ऊँचाइयों पर ले जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह समारोह केवल औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के सपनों, संकल्पों और संघर्षों का उत्सव है। उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बहुविषयक अध्ययन, कौशल आधारित शिक्षण, चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और आधुनिक पाठ्यचर्या जैसी व्यवस्थाओं को लापू करने की सराहना की, जिससे छात्र वैश्विक अवसरों का लाभ उठा सकें।

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के मार्गदर्शन में बने इस राज्य ने शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि दीक्षांत समारोह छात्रों के परिश्रम, संघर्ष और लगन का सम्मान है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में अकादमिक बैंक ऑफ

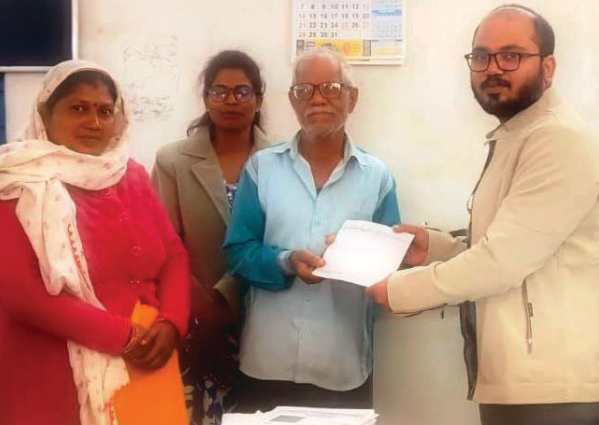
डिजिटलइंजेशन की ओर कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि विवि में डिजिटलइंजेशन के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा फॉर्म, ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री प्रमाणपत्र जैसी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। इस नई प्रणाली से छात्रों को सरल, पारदर्शी और त्वरित सेवाएँ मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि पीएम उषा कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता नए प्रयोगशालाओं, स्मार्ट कक्षाओं, डिजिटल लाइब्रेरी और आधुनिक अकादमिक अवसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी इससे विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और नवाचार को सुनिश्चित कर सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों को राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक संरचना, भाषा-साहित्य और तकनीकी नवाचार जैसे क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शोध को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को ज्ञान, अनुशासन और प्रेरणा का एक उत्सव प्रदान किया और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और नवाचार की प्रतिबद्धता को उजागर किया।

क्रेडिट का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है तथा 20 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिससे शैक्षणिक अधोसंरचना और अधिक मजबूत होगी। अतिथियों ने विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका कन्हार का भी विमोचन किया।

महिला समूह की सदस्य के परिजन को पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना से मिला दो लाख रुपये का लाभ



श्रीकंचनपथ न्यूज़

रायपुर। ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लगातार सकारात्मक परिणाम दे रही है। यह योजना विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की सदस्य महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा का मजबूत माध्यम बनती जा रही है। इसी कड़ी में मनेन्द्रगढ़- चिरमिरी-भरतपुर जिले के ग्राम पंचायत मनवारी के जीवन माँ दुर्गा महिला स्वयं सहायता समूह की सक्रिय सदस्य रही स्वर्गोय इन्द्रावती विश्वकर्मा के परिवार को योजना के तहत बीमा का लाभ प्रदान किया गया। श्रीमती इन्द्रावती की स्वाभाविक निधन के बाद उनके नामित वारिस रामजया विश्वकर्मा को योजना के तहत दो लाख रुपये की बीमा दावा राशि प्रदान की गई।

आर्थिक कठिनाइयों के समय यह सहायता परिवार के लिए एक बड़ी राहत बनी, जिससे वे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा

करने तथा भविष्य की योजना बनाने में समर्थ हो सके। इस बीमा दावा प्रक्रिया की सुगम और समयबद्ध तरीके से पूरा करने में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बी.आर.एल.एम.) के अधिकारी-कर्मचारी कैडर और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, शाखा केल्लहारी के प्रबंधक राजकमल राजीव का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनकी सक्रिय पहल ने परिवार तक योजना का लाभ समय पर पहुँचाने में अहम भूमिका निभाई।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना न केवल महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि अल्पस्थायित परिस्थितियों में परिवार को संबल देकर सामाजिक सुरक्षा को भी मजबूत बनाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को इस योजना से जुड़ने हेतु लगातार जागरूकता कार्यक्रम, समूह बैठकों और परामर्श शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। यह पहल एसएचजी की दीर्घियों और उनके परिवारों के लिए नई उम्मीद और विश्वास का आधार बन रही है।

वर्षों बाद खेल मैदान में लौटीं महिलाएं, बस्तर ओलंपिक बना जड़ों से जोड़ने का माध्यम

श्रीकंचनपथ न्यूज़



तक पहुँचना हम सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है। बस्तर ओलंपिक में सरोज पोडियाम और उनकी टीम ने रस्साकसी में दमदार प्रदर्शन करते हुए संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन हासिल किया है। टीम की इस उपलब्धि से पूरे परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। सरोज कहती हैं कि हम सभी महिला साथी बहुत खुश हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का धन्यवाद, जिन्होंने हमें अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच दिया। इस बार पूरा प्रयास रहेगा कि हम संभाग में अपने जिले को जीत

दिलाएं। बस्तर ओलंपिक ने हमें दोबारा खेलने का मौका दिया और आस-पास की सभी महिला साथी भी शामिल हुईं। सरोज पोडियाम का परिवार माओवादी हिंसा से प्रभावित रहा है। वर्ष 2009 में नक्सलियों द्वारा उनके ससुर की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद परिवार गहरे संकट में आ गया। घटना के बाद शासन ने नवा विहाय योजना के तहत सुकमा में उन्हें आवास उपलब्ध कराया तथा उनके पति राकेश को नगर सैनिक के रूप में पदस्थ कर परिवार को संबल दिया।